प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी. /93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 23 – 30 अगस्त 2021 मूल्य पांच रुपए

स्वर्णिम रथ यात्रा से पहले आया मुकेश अग्निहोत्री का जनता के नाम खुला पत्र

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखकर आम आदमी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है क्योंकि जब संसद से लेकर विधानसभा तक सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार न हो। संसद में बिना बहस के बिल पास हो जाये और देश के प्रधान न्यायधीश को अपनी चिन्ता सार्वजनिक करनी पड़े तो स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यवस्था में आम आदमी और उसके सवालों के लिये कहीं कोई मंच नहीं रह गया है। ऐसे में किसी भी संवदेनशील नेता के लिये जनता के दरबार में गुहार लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्योंकि इसी जनता को अच्छे दिन आने का सपना दिखाकर उसका विश्वास जीतकर यह सरकार सत्ता में आयी थी। सात साल सत्ता भोगने के बाद भी जो सरकार विपक्ष से ही सवाल करे क्या उससे यह नहीं पूछा जाना चाहिये कि क्या उसने सत्ता संभालने पर देश की स्थिति को लेकर कोई श्वेत पत्र इस जनता के सामने रखा था शायद नहीं। आज अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिये अपने संख्या बल की ताकत पर विपक्ष की आवाज को दबाना ज्यादा देर नहीं चलेगा।

आज जयराम सरकार अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन करने जा रही है। पूरे प्रशासन को इस यात्रा की तैयारी पर लगा दिया है। अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा और अब स्वर्णिम रथ यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब प्रदेश की जनता को कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बराबर परोसा जा रहा है। कोरोना के कारण प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान पिछले वर्ष मार्च से लेकर अब तक बन्द चले आ रहे हैं। बच्चों और अध्यापकों को मोबाईल पर आश्रित कर दिया गया है। जिस मोबाईल का ऑप्रेशन पैट्रोल पम्पों पर प्रतिबन्धित है और डाक्टर इसके आन्तरिक प्रयोग से बच्चों को बचने की नसीहत देते हैं क्योंकि इससे उनकी ऑखे प्रभावित होगी लेकिन आज सरकारी आदेश से सबको इस पर आश्रित बना दिया गया है। यदि आने वाले समय में पांच प्रतिशत भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो क्या एक नयी समस्या को न्योता नहीं दिया जा रहा है। कोरोना का अभी तक कोई ईलाज सामने नहीं आया है। फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि उनका अन्य बिमारियों के लिये ही उपचार किया जा रहा है। कोरोना में जितने लोगों की मोत हुई है उसमें सरकार के अपने आंकड़ो के अनुसार ही 80% से अधिक मौतें अन्य बिमारियों से हुई है। जब 24 मार्च 2020 को लाकडाऊन लगाया गया था और उसके कारण सारे अस्पताल भी खाली कर दिये गये थे तब लम्बे समय तक लोग बिना ईलाज के रहे थे। उन लोगों में से कितने कोरोना के कारण अब अपनी जान गंवा चुक हैं इसका कोई अध्ययन आंकड़ा सरकार के पास नहीं है।

कोरोना को लेकर सरकार की समझ अभी यहीं तक पहुंची है कि इसका संक्रमण शादी–ब्याह के समारोहों से फैलता है और राजनीतिक रैलियों से नहीं। यह आम आदमी के सामने आ चुका है कि कोरोना काल में बंदिशों के दौरान राजनीतिक गतिविधियां बराबर जारी रही है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कितने लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे और भीड़ में सोशल डिस्टैंन्सिग की कितनी पालना हो रही थी यह सब जनता के सामने आ चुका है। अब जो रथ यात्रा प्रस्तावित है उसमें भी इसी तरह का आचरण रहेगा यह तय है। ऐसे में जब सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है तब जनता को इस सब पर विचार करना होगा। इसी आश्य के साथ नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की जनता के नाम खुला पत्र लिखकर उसका ध्यान आकर्षित किया है।

हाय महंगाई : दुहाई-दुहाई

मेरे प्यारे प्रदेशवासियो
नमस्कार

मैं आपका मुकेश अग्निहोत्री आपसे मुखातिब हूं। मुझे उम्मीद है कि कोरोना महामारी के दौर में परमात्मा के आशीर्वाद से आप स्वस्थ और तंदरुस्त होंगे। कोरोना के कारण सैकड़ों प्रदेशवासी अकाल काल का शिकार हो गए। मैं परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। कोरोना का खतरा टला नहीं है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। आपसे अपील है कि एहतियात बरतें ताकि आप, आपका परिवार, गांव, शहर और हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे।

प्रदेशवासियो मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। कोरोना महामारी के दौर में महंगाई हमें बेहाल कर रही है। कोरोना काल में लाखों युवाओं का रोजगार आपकी आंखों के सामने छिना है। आपके काम-धंधे बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन सरकार ने किसी की सुध नहीं ली। महंगाई की समस्या जितनी गंभीर है, केंद्र की मोदी और हिमाचल की जयराम की सरकार उतनी ही अगंभीर हैं। उनके पास महंगाई रोकने के उपाय नहीं है। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से जनता परेशान है। लोग राहत के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे है।

महंगाई की रफ्तार खतरें की सीमा लांघ चुकी है। पेट्रोल-डीजल, सरसो तेल, रसोई गैस, खाने-पीने की वस्तुओं समेत तमाम जरूरी चीजों की कीमतों में अंधाधुंध वृद्धि से आम आदमी खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। मगर अच्छे दिन लाने के झूठे वादे करने वाली प्रदेश और केंद्र सरकारें सत्ता के नशे में डूबकर संवेदनहीन बनी हुई हैं। जनता की पीड़ा महसूस करने की बजाय भाजपा के मंत्री और नेता जुमलेबाज बने हुए हैं। पिछले दो महीनों में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब पेट्रोल-डीजल महंगा न हुआ हो। यह तब है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है। जनता को याद है कि यूपीए सरकार के समय जब कभी पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस के दाम बढ़ते थे तब अर्धनग्न होकर खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेता आज अंधे बने हुए हैं।

प्यारे प्रदेशवासियो, हिमाचल के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कहते नहीं थकते हैं कि यहां डबल इंजन की सरकार है। जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन डबल इंजन की इस सरकार ने प्रदेशवासियों का जीना दूभर कर दिया है। सरकार की दूलमूल नीतियों ने गरीब-आम-खास सभी का बजट बिगाड़ दिया है। भाजपा नेता आज भी महंगाई के लिए पूर्व सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल-रसाई गैस भारत में बिक रही है। महंगाई ने तमाम रिकार्ड तोड़ डाले हैं। मोदी सरकार ने दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक टैक्स लगाने का रिकार्ड भी बनाया है। भाजपा सरकारों और नेताओं का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। यूपीए सरकार में 60 प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 100 रुपये और 50 रुपये में मिलने वाला डीजल 95-96 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रसोई गैस सिलेंडर का दाम आज 900 रुपये के पार हो गया है जबकि यूपीए सरकार के समय 425 रुपये था। पिछले छह माह में रसोई गैस 150 रुपये प्रति सिलेंडर महंगी हुई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण खाने के तेल, अनाज, हरी सब्जियों, फलों समेत सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले एक साल में खाने के तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। जुलाई, 2021 में तो खाने के तेल की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तर पर थीं। जुलाई, 2020 में 90-100 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला तेल आज 190-200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि हर तरह के खाने का तेल 20 से 55 फीसद महंगा हुआ है। गरीबों का सहारा कही जाने वाली दालों पर भी संकट है। पिछले एक साल में दालें बहुत महंगी हुई हैं। एक साल पहले 90-95 रुपये प्रति किलो बिकने वाली अरहर दाल अब 120-125 रुपये प्रति किलो में मिल रही है। उड़द, मूंग, मसूर, चना दाल के दाम भी आसमान छू रहे हैं।

खुद को जनता का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाली भाजपा महंगाई के मुद्दे पर जन जागरण अभियान, पदयात्राएं और अनशन करने से बच रही है। क्या झूठ बोल कर सत्ता हथियाना ही भाजपाइयों का एकमात्र एजेंडा है। जब भाजपा सत्ताविहीन होती है तब जनहित और महंगाई की दुहाई देकर उसके नेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं, पर सत्ता मिलते ही सब भूल जाते हैं। जनता यह नहीं भूल सकती कि अच्छे दिन लाने की दुहाई देकर भाजपा नेताओं ने महंगाई पर लगाम लगाने और सुशासन का सपना दिखाया था। पर सत्ता मिलते ही उन्होंने जनता को छलने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट कर दी।

हिमाचल में बेरोजगारी रिकार्ड स्तर पर है। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भता फ्रीज कर दिया गया है। प्रदेश में बिजली के भारी-भरकम बिलों से जनता परेशान है। नए मीटर लगवाना लोगों की पहुंच से बाहर है। पानी के बढ़े बिलों से जनता दुखी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हिमाचल में पैदा होने वाली बिजली बाहरी राज्यों को सस्ती बेची जा रही है जबकि प्रदेशवासियों को महंगी। यही स्थिति सीमेंट की भी है। हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता है जबकि भाजपा राज में हिमाचल में पिछले तीन साल में सवा सौ रुपये प्रति बोरी महंगी होकर इसकी कीमत चार सौ से पार हो चुकी है। असल में प्रदेश की भाजपा सरकार को जनता की परेशानी से कोई लेना-देना नहीं है। हिमाचल भाजपा सरकार जनहित भूल चुकी है। हिमाचल में आज सस्ता राशन योजना का भी भट्ठा बैठ गया है। सरकारी डिपुओं में मिलने वाली दालें, तेल, चीनी और नमक सब महंगे हो गए हैं। जनता को राहत देने की बजाय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मोदी के गुणगान में व्यस्त हैं।

भाजपा और उसकी सरकार को याद रखना चाहिए कि जनाक्रोश बड़े से बड़े सत्ता सिंहासन हिला देता है। महंगाई के मुद्दे पर पहले भी कई सरकारें गई हैं। गरीब की 'आह' सब स्वाह कर देती है। महंगाई और भाजपा सरकार के झूठे वादों से त्रस्त जनता हिमाचल में भाजपा को घुटनों पर ला देगी। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से दुखी आम आदमी की पीड़ा को आवाज देने से कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी है और न हटेगी। सरकार के हर जुल्मो-सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के अपने धर्म को कांग्रेस निभाएगी। मुझे भरोसा है कि महंगाई समेत आपके समक्ष पेश आ रही समस्याओं पर आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इस उम्मीद के साथ बात खत्म करूंगा कि आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहेगा।

जयहिंद-जय हिमाचल

आपका अपना
मुकेश अग्निहोत्री

Scanned with

जब बैंक लोक पाल के आदेशों की भी अनुपालना न करे तो पीड़ित के पास क्या विकल्प रह जाता है

शिमला/शैल। जब बैंक प्रबन्धन बैकिंग लोकपाल के आदेश की भी अनुपालना करने में टालमटोल करे तब बैंक की ही मिली भगत से ही किसी निर्दोष के खिलाफ रचे गये फ्रॉड के मामले में पीड़ित को दर- दर की ठोकरें खाने पर मज़दूर कर दिया जाये तो ऐसी व्यवस्था को क्या संज्ञा दी जाये यह सवाल ऊना की रकड़ कालोनी के निवासी और प्रदेश के साहित्यिक जगत के एक चर्चित नाम कुलदीप शर्मा के साथ हुए फ्रॉड से अब जनता की अदालत तक पहुंच कर सारे संवद्ध पक्षों से जवाब मांग रहा है। यह सवाल उस समय और भी अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री और वित्त मन्त्री आये दिन लोगों को बैंक से कर्ज लेकर अपना काम चलाने की सलाह दें। बैंकों की ज्यादतीयों से पीड़ित कितने लोग आत्म हत्याएं कर चुके हैं इन आंकड़ों को शायद दोहराने की आवश्यकता नहीं है। साहित्यकार अपनी सरलता के कारण किसी की भी तकलीफ पर उसकी मद्द करने के लिये तैयार हो जाता है यह उसका स्वभाविक गुण है। इसी गुण के कारण कुलदीप शर्मा एक शाहिद हुसैन और राकेश पाल के षडयन्त्र का शिकार हो गये क्योंकि इसमें केनरा बैंक का स्थानीय प्रबन्धन भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा था और इन सबकी नजर कुलदीप की संपति पर थी।

इस संपत्ति को हथियाने के लिये शाहिद और राकेश पाल ने उनके उद्योग पारस होम सप्लाईन्स के नाम आया एक लाख दस हजार डालर का सप्लाई आर्डर दिखाकर इस आर्डर को पूरा करने के लिये बैंक से कर्ज लेने की जरूरत दिखायी और इस कर्ज के लिये कुलदीप से गारंटी देने की मद्द मांगी। केनरा बैंक के प्रबन्धक ने भी इस गारंटी के लिये कुलदीप को पूरी आश्वस्त किया। यह उद्योग CGTSME योजना के तहत जून 2013 में स्थापित हो चुका था और इस कर्ज की आवश्यकता दिसम्बर 2013 में आयी। इसलिये शक करने का कोई कारण सामने नहीं दिखा। कुलदीप इसके लिये तैयार हो गये और संपत्ति के पेपर बैंक को दे दिये गये। लेकिन बाद में शाहिद और राकेश पाल मे बैंक के सहयोग से पारस होम एपलाईन्स के नाम से ही एक और जाली उद्योग इकाई शाहिद की पत्नी के नाम दिखाकर उसको कर्ज दे दिया और उसमें कुलदीप शर्मा की संपत्ति के पेपर प्रयोग कर लिये गये।

जब कुलदीप शर्मा को इस फर्जीवाडे का पता चला तब उन्होंने बैंक, स्थानीय प्रशासन तक से इनकी शिकायत की। पुलिस मे मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार तक कर किया लेकिन बैंक ने कुलदीप शर्मा को गारंटी से मुक्त नहीं किया। बैंक के इस आचरण के खिलाफ चण्डीगढ़ स्थित बैंकिग लोकपाल के पास मामला पहुंचा। लोकपाल ने केनरा बैंक को दोषी करार देते हुए कुलदीप को इस गारंटी से मुक्त करने के आदेश सुनाये। बैंक प्रबन्धन ने भी इन आदेशों पर लोकपाल के समक्ष लिखित में सहमति दी है। 16-3-20 को लोकपाल ने यह आदेश पारित किये हैं लेकिन आज तक बैंक प्रबन्धन इसकी अनुपालना नहीं कर रहा है। क्या अराजकता का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या बैंक प्रबन्धन इस तरह पीड़ित को कोई और हताशा का कदम उठाने के लिये बाध्य नही कर रहा है।

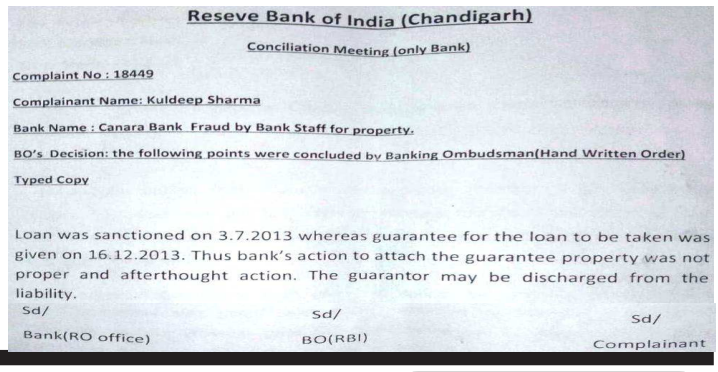

Reseve Bank of India (Chandigarh)

Conciliation Meeting (only Bank)

Complaint No : 18449

Complainant Name: Kuldeep Sharma

Bank Name : Canara Bank Fraud by Bank Staff for property.

BO's Decision: the following points were concluded by Banking Ombudsman(Hand Written Order)

Typed Copy

Loan was sanctioned on 3.7.2013 whereas guarantee for the loan to be taken was given on 16.12.2013. Thus bank's action to attach the guarantee property was not proper and afterthought action. The guarantor may be discharged from the liability.

Sd/ Bank(RO office)

Sd/ BO(RBI)

Sd/ Complainant

लाहौल की समृद्ध संस्कृति से प्रभावित हुए राज्यपाल आर्लेकर

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, परम्पराएं और रीति-रिवाज़ समृद्ध हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि यहां के लोगों ने अपनी इस पहचान को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि वह यहां कि संस्कृति से प्रभावित हुए हैं।

राज्यपाल लाहौल-स्पीति के काजा में उनके सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें लगा कि हिमाचल सही मायनों में सुदूर क्षेत्रों में बसता है। वह कोशिश करेंगे कि राज्य के हर जिले का दौरा कर लोगों से मिलें। हिमाचल की संस्कृति को नजदीक से समझने के साथ-साथ इस तरह वह लोगों की समस्याओं को भी जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां उनसे मिले लाहौलवासियों ने भी अपनी कुछ समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया है और वह उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। दुनिया को आकर्षित करते पहाड़ और बौद्ध संस्कृति और स्वच्छ वातावरण सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां नियोजित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से रोजगार भी बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां भी तेज़ होंगी।

राज्यपाल ने इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य का आनंद लिया। लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी उपस्थित थीं।

इससे पूर्व, एडीएम मोहन दत्त ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को पारम्परिक वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने स्थानीय प्रशासन के साथ भी बैठक कर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की हैं, जिनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए।

राज्यपाल ने लांगचा, कौमिक और हिक्कमि गांवों का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने लांगचा में छेरिंग डोलमा और गटूक छोडन को गृहिणी सुविधा के तहत गैस कनैक्शन व चूल्हा विरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को खाना पकाने के चुल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाने तथा पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गत तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना के तहत 2.85 लाख महिलाओं को नि:शुल्क गैस कुनैक्शन उपलब्ध करवाए हैं और इसी का परिणाम है कि दिसम्बर 2019 में हिमाचल प्रदेश को चूल्हा धुआ मुक्त राज्य घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की। राज्यपाल ने ताबो और की-गोम्पा का दौरा भी किया।

राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ सेब खरीद में अपना रहा पारदर्शिता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2020 में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए 125 खरीद केन्द्रों पर 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम सेब की खरीद की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खरीदे गए सेब की शिमला जिले के ऑटी और सोलन जिला के परवाणु में नियमानुसार नीलामी की जा रही है। नीलामी समितियों में हिमफैड के अधिकारियों के अतिरिक्त बागवानी विभाग तथा विपणन बोर्ड के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

नीलामी प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए उड़नदस्तों तथा निरीक्षण दलों का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सेब फसल की अधिक उत्पादकता हुई है लेकिन साथ ही ओलावृष्टि से वर्ष 2019-20 के अपेक्षा इस वर्ष अपेक्षाकृत सात गुणा फसल खराब हुई है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा वर्ष 2020 में 20 जुलाई 2020 से 24 अगस्त 2020 तक 17914 सेब की बोरियां खरीदी गई थीं जबकि इस वर्ष इसी अवधि के दौरान 124000 सेब की बोरियां खरीदी गई हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि सेब की खराब हालत के दृष्टिगत अधिक समय तक इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के कारण दूसरे राज्यों से व्यापारी विक्रय केन्द्रों पर कम संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न मंडियों में ए व बी ग्रेड का सेब भी कम दरों पर बेचा जा रहा है। इसके बावजूद हिमफैड यह सुनिश्चित कर रहा है कि सेब के क्रय-विक्रय में पूर्णत: पारदर्शिता अपनाई जाए।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि जन्माष्टमी देशवासियों का एक पावन पर्व है, जिसे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय राम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हिन्दू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है।

राष्ट्रीय जल मिशन के अन्तर्गत 'कैच द रेन' अभियान शुरू

शिमला/शैल। जी. अशोक कुमार, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जल संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए तथा हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संग्रहण, परामपरिक जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन गतिविधियों व जागरूकता आदि के लिए वृहद प्रबन्ध योजना बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को मनोरम सौन्दर्य से नवाजा है तथा यहां पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन पर्यावरण में निरंतर बदलाव के कारण स्थिति गम्भीर होती जा रही है तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने हमें इस दिशा में सोचने पर बाध्य कर दिया हैं।

उन्होंने कहा कि हमें वर्षा की प्रत्येक बूंद का संग्रहण करने तथा जल के तीव्र प्रवाह को रोकने की आवश्यकता है। इससे पानी की कमी की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में पानी प्रदान करने तथा निचले क्षेत्रों में बाढ़ से उपजाऊ भूमि की सुरक्षा में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रें में पंचायतों के माध्यम से वृहद अभियान चलाने की आवश्यकता है।

अशोक कुमार ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन के अंग के रूप में 'कैच द रेन' नाम से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल मंत्र है 'वर्षा की हर बूंद, जहां गिरे, जब गिरे, उसका संग्रहण करें'। उन्होंने कहा कि राज्य में अभियान को गति मिली है और काफी कार्य किया गया है, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में इस विषय पर जागरूकता लाने का आग्रह किया ताकि इसे व्यापक रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने पूजा सोनी और साक्षी को आर्थिक सहायता प्रदान की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं के गांव कोठी निवासी पूजा सोनी और जिला मण्डी की तहसील सरकाघाट के गांव रामनगर की साक्षी के परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सहायता प्रदान कर उच्च मानवीय मूल्यों का परिचय दिया है।

मुख्यमंत्री को अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से अवगत करवाते हुए साक्षी ने कहा कि वह गरीब परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। उनके पिता मजदूरी करते हैं जबकि मां बीमार रहती हैं। वह और उनकी बहन महक अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती है परन्तु धन के अभाव ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई हो रही है।

इसी प्रकार की आर्थिक तंगी की समस्या को लेकर पूजा सोनी जब मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मिलीं तो मुख्यमंत्री ने उन्हें भी निराश नहीं किया। पूजा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी दिव्यांग है। उन्होंने कहा कि आजीविका का कोई निश्चित साधन न होने के कारण उन्हें बेटी का ईलाज करवाने में मुश्किल हो रही है। मुख्यमंत्री ने पूजा और साक्षी की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की।

पूजा और साक्षी ने इस आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

किन्नौर को सेब विकास कलस्टर के रूप में विकसित करने पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपये: महेंद्र सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने एचपीएमसी निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से जिला किन्नौर को सेब विकास के लिए क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और एचपीएमसी को क्लस्टर विकास एंजेसी का कार्य सौंपा गया है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंर्तगत पूर्व फसल उत्पादन कार्यकलापों पर बल दिया जाएगा, जिसके अंर्तगत मृदा परीक्षण, पत्ता विश्लेषण, प्लांट हेल्थ क्लीनिक सुविधाएं स्थापित की जाएगी। उत्पादन के तौर-तरीके जैसे उच्च घनत्व पौध रोपण, एकीकृत रोग कीट प्रबंधन कार्य किए जाएंगे और फसल उत्पादन, पैकिंग हाऊस, प्रोसेसिंग इकाईयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा विपणन के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे, जिनमें मार्केट यार्ड, अपग्रेडेशन, विपणन के नए चैनल स्थापित करना और किन्नौर की ब्रांडिग पर विपणन को बढ़ावा देना शामिल है। इन कार्यों के लिए कृषक उत्पादक समूह का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपये की सेब आर्थिकी वाले किन्नौर जिला में 10,400 हेक्टेयर भूमि पर सेब की बागवानी की जा रही है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर जिला मण्डी के जड़ोल व जिला सोलन के जाबली में एचपीएमसी के उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय केन्द्र निर्मित किए जा रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कुंडली स्थित भूमि एवं कोलकाता में एचपीएमसी की भूमि पर पीपीपी मोड पर विकास कार्य आरम्भ किए जाएंगे। जड़ोल, टिक्कर जिला शिमला में एचपीएमसी द्वारा पेट्रोल पंप भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी परियोजना के अंर्तगत 266 करोड़ रुपये की लागत से 15 विकास कार्य किए जा रहे हैं। शिमला जिले के पराला में निर्माणाधीन फल विधायन संयंत्र में मिनरल वाटर की बॉटलिंग के अतिरिक्त कागज़, चिप्स, पशुचारा आदि तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जड़ोल (सुन्दरनगर) स्थित फल विधायन संयंत्र में आम, नीम्बू, टमाटर पर आधारित फल विधायन की गतिविधियों में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि एचपीएमसी द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए एंड्रायड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया गया है। इसके फलस्वरूप सूचना एकत्रीकरण एवं इस योजना के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि अब एचपीएमसी के उत्पाद बिक्री के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य एवं खाद्य आपूर्ति निगम की उचित मूल्यों की दुकानों पर भी उपलब्ध होंगे, जिसके लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेब के लिए वर्ष 2021 में मण्डी मध्यस्थता योजना के अंर्तगत निगम द्वारा 169 में से 160 क्रय केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 7787 मी.टन सेब की खरीद की गई है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि स्विटज़रलैंड की जीवौदान इंडिया प्रा. लिमिटेड के साथ 112.320 मी.टन एप्पल जूस बिक्री के लिए अनुबंध किया गया है जिसके तहत अभी तक कंपनी को 44.280 मी.टन जूस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन एवं वीटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अन्तर्गत हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन एक वर्ष के भीतर हरियाणा राज्य में दो हजार हर हित खुदरा स्टोर खोलगा, जिससे एचपीएमसी के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने 100 प्रतिशत प्राकृतिक एप्पल जूस का एक लीटर टैट्रापैक बाज़ार में उतारा है।

आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को 32 आईसीयू पेशेंट मॉनिटर्ज भेंट किये

शिमला/शैल। आईसीआईसीआई फाउंडेशन और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अस्पतालों में मरीजों के उपयोग के लिए 32 आईसीयू पेशेंट मॉनिटर्ज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किए गए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस पुनीत कार्य के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन और बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान प्रदेश के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

मंत्रिमण्डल में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमण्डल की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित

करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डॉलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डॉलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।

शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में संवर्द्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मल निकासी सेवाएं प्रदान करना है।

इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 कि.मी की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति प्रणाली में स्तरोनन्त करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, शिमला के मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मलनिकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ति और मलनिकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी और वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस निधि को प्राप्त करेगा।

मंत्रिमण्डल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया।

जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रक्कड़ को 24 घण्टे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन स्थान और कैन्टीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।

बागवानों को मंडियों की वास्तविकता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन के दृष्टिगत बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण (एचपीएमसी), कृषि उत्पाद विपणन निगम (एपीएमसी), हिमफैड और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।

सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मंडियों में सेब की ढुलाई को नियन्त्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बागवानों को मंडियों की वास्तविकता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे चिन्तित न हों। उन्हें राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को बेहतर दाम मिल रहे हैं इसलिए बागवानों को प्रदेश सरकार पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।

शहरी विकास मंत्री ने उपायुक्त शिमला को सेब के सीजन के दृष्टिगत सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त को ठियोग के क्यारटू गांव में तीन दिनों के भीतर सड़क के रख-रखाव के निर्देश दिए।

सुरेश भारद्वाज ने सेब के सीजन के दौरान यातायात की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। पुलिस अधीक्षक शिमला मोनिका भुटुंगरू ने मंत्री को आश्वासन दिया कि सेब सीजन के दौरान विशेषकर मंडियों के निकट यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती के सभी प्रबन्ध किए जा चुके हैं।

एचपीएमसी के अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि मंडियों में अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए मंडियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।

प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केलांग में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कारगा में नई आईटीआई खोलने, गुमरांग व लोट में स्वास्थ्य उप केन्द्र तथा रारिक में प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा की। उन्होंने शिशुर गोम्पा के लिए 30 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की भी घोषणा की। उन्होंने केलांग में क्षतिग्रस्त ओवरहैड स्वागत द्वार के पुनर्निर्माण के लिए 30

लाख रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से विशेषज्ञ चिकित्सकों को सप्ताह में दो दिन के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में तैनात किया जाएगा।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल-स्पीति के केलांग में 41 करोड़ रुपये की लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास किए, जिनमें 1.34 करोड़ की एक विकासात्मक परियोजना का लोकार्पण तथा लगभग 39.48 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं।

जय राम ठाकुर ने 1.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित योचे-बोलतोजिंग सड़क का लोकार्पण किया। उनहोंने 12.24 करोड़ रुपये की लागत से केलांग में शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं पार्किंग, 13.69 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजना केलांग के संवर्धन कार्य, 1.10 करोड़ रुपये की लागत से केलांग के लिए फायर हाइड्रेंट, 1.33 करोड़ रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना कारदंग, 85 लाख रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना टोजिंग, 1.26 करोड़ रुपये की लागत से जिस्पा में बाढ़ नियंत्रण कार्य, 6.59 करोड़ रुपये की लागत से गौशाल में बाढ़ नियंत्रण कार्य, 45 लाख रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना कवारिंग, 1.19 करोड़ रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना बरगुल और 78 लाख रुपये की लागत से बहाव सिंचाई योजना रोगलिंग का शिलान्यास किया।

तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जनजातीय क्षेत्रों की विकासात्मक मांगों पर सदैव विचार करने के लिए आभार व्यक्त किया।

नई तकनीक और सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएः डॉ कौशल

शिमला/शैल। राज्य के बागवानी विकास अधिकारियों (एचडीओ) के लिए डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के विस्तार शिक्षा निदेशालय, द्वारा 'फलों की उत्पादकता में वृद्धि' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बागवानी विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 24 एचडीओ ने भाग लिया। प्रशिक्षुओं को कैनोपी विकास, बगीचों का प्रबंधन, मिट्टी और पौधों का पोषण, जल संचयन संरचनाओं के साथ-साथ फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उच्च घनत्व वाले सेब के बागानों में उपयोग की जा रही नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी के लिए प्रशिक्षुओं ने केवीके सोलन का भी दौरा किया।

समापन समारोह के दौरान कुलपति डॉ. परविंदर कौशल ने प्रतिभागियों से सक्रिय बनने और सरकारी योजनाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में की जा रही नवीन तकनीकों और अनुसंधान का लाभ किसानों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लाईन विभाग के कार्यरत युवा द्वारा फील्ड में किए जा रहे कार्यों को देखकर खुशी होती है, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों, क़िस्मों का चयन, प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने की चुनौतियों से ठीक से निपटने की जरूरत है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी और समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार के दोहरे लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

डॉ. कौशल ने कहा कि राज्य में कई प्रतिष्ठित कृषि-बागवानी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे न केवल किसानों को लाभ बल्कि बुनियादी ढांचे का विकास भी हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं, विशेष रूप से ज्यादा शेल्फलाइफ वाले उत्पाद। यह बताते हुए कि विश्वविद्यालय ने नौणी में चार साल के उच्च घनत्व वाले सेब के बगीचे में 42 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादकता हासिल की है, डॉ. कौशल ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसानों की फील्ड में उसी सफलता को दोहराया जाए। उन्होंने प्रतिभागियों से विश्वविद्यालय और कृषि बागवानी क्षेत्र की नवीनतम जानकारी के बारे में जानने का आग्रह किया।

उन्होंने ग्रामीण युवाओं को हाई-टेक नर्सरी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया। विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित कई प्रोटोकॉल का प्रसार इस क्षेत्र में मददगार हो सकता है।

उन्होंने अधिकारियों से पुराने बगीचों में उचित प्रुनिंग की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कृषि उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर समर्थन प्रदान करने के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करने के साथ-साथ परागण सेवाओं के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. दिवेंद्र गुप्ता ने यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया कि किसान विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित विभिन्न फलों और सब्जियों के लिए नवीनतम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अपनाए। उन्होंने बताया कि महामारी के बाद विश्वविद्यालय में यह पहला ऑफ़लाइन प्रशिक्षण था और विश्वविद्यालय पिछले कई महीनों से ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. मनिका तोमर ने प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न आधिकारिक सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म के बारे में अवगत कराया जहां तकनीकी वीडियो नियमित रूप से साझा किए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक डॉ. सी.एल. ठाकुर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जो अपने कर्तव्यों से बचते है, वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण–पोषण नहीं कर पाते।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या मौद्रीकरण के दावों पर विश्वास किया जा सकता है

मोदी सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्गो, रेलवे संपत्तियों, बिजली की ट्रांसमिशन लाईनो और हाइड्रो, सोलर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं का मौद्रीकरण करके छः लाख करोड़ जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये वित्त मन्त्री सीतारमण ने एनएमपी योजना की घोषणा की है और इसके लिये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सचिव कमेटी का गठन किया गया है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि इसके लिये इन संपत्तियों की ज़मीन नहीं बेची जायेगी। बल्कि इसके तहत इन संपत्तियों का पूर्ण मौद्रिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये प्राईवेट सैक्टर का सहयोग लिया जायेगा। इसमें 90,000 कि.मी. राष्ट्रीय उच्च मार्गो से 1.6 लाख करोड़, 400 रेलवे स्टेशनों, 150 ट्रेनो और अन्य रेलवे संपतियों से 1.5 लाख करोड़, 67000 करोड़ ट्रांसमिशन लाईनों, 32,000 करोड़ एनएचपीसी, एनटीपीसी और नवेली लिंगनाइट विद्युत परियोजनाओं से जुटाया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम तथा सार्वजनिक उपक्रमों के रैस्ट हॉऊसों को भी मौद्रीकरण में शामिल किया गया है। विपक्ष इसे इन संपत्तियों को प्राईवेट सैक्टर को बेचना करार दे रहा है। विपक्ष के इस आरोप के जवाब में सरकार ने कहा है कि प्राईवेट सैक्टर को केवल चार वर्ष के लिये ही यह संपत्तियां दी जा रही हैं और उसके बाद इन्हें वापिस ले लिया जायेगा।

सरकार के आश्वासन और विपक्ष के आरोप के परिप्रेक्ष में मौद्रीकरण की नीति और देश की आर्थिक स्थिति को समझना आवश्यक हो जाता है। मानेटरी पॉलिसी हर देश का केन्द्रिय बैंक लाता है। इस नाते इसकी घोषणा आरबीआई को करनी चाहिये थी परन्तु यह घोषणा वित्त मन्त्री के माध्यम से आयी है। मानेटरी पॉलिसी वह प्रक्रिया है जिसके तहत केन्द्रिय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति का प्रबन्ध करता है। इसके माध्यम से कीमतों और ग्रोथ में स्थिरता बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्राईवेट सैक्टर का सहयोग लिया जाता है और इसका प्रभाव कर्ज के मंहगा होने तथा ब्याजदरों पर पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि ऐसे क्या कारण हो गये कि अर्थव्यपस्था में पैसे की आपूर्ति करने के लिये सरकारी संपत्तियों का इस तरह मौद्रीकरण करने की अनिवार्यता आ खड़ी हुई है। क्या इन संपतियों से इस समय सरकार को आमदन नहीं हो रही थी? क्या इन संपतियों से छः लाख करोड़ जुटा कर अर्थव्यवस्था में डालने से यह संकट हमेशा के लिये टल जायेगा? जब प्राईवेट सैक्टर इनमें निवेश करके सरकार को भी छः लाख करोड़ देगा और अपने लिये भी निश्चित लाभ कमायेगा तो क्या इसका असर उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा? क्या इससे सड़क और रेल दोनों से यात्रा करना स्वभाविक रूप से ही मंहगा नहीं हो जायेगा। जब ट्रांसमिशन लाईने और विद्युत परियोजनाएं दोनो ही प्राईवेट के पास चली जायेंगी तो क्या यह सबकुछ और मंहगा नहीं होगा। क्या सरकार द्वारा इस नीति को मौद्रीकरण का नाम देने से इनकी मंहगाई का असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। फिर जब चार वर्ष के लिये ही इन संपत्तियों को प्राईवेट सैक्टर को देने की बात की जा रही है तो यह सैक्टर इन्हे सुधारने के लिये इनमें निवेश ही क्यों करेगा?

मोदी सरकार ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी उस समय मार्च 2014 में केन्द्र सरकार का कुल कर्ज 53.11 लाख करोड़ था। यह कर्ज आज बढ़कर 101.3 करोड़ हो गया है। जिस अनुपात में सरकार का कर्ज बढ़ा है क्या उसी अनुपात में राजस्व में भी बढ़ौत्तरी हुई है? शायद नहीं। फिर क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिये कि यह कर्ज कहां निवेश किया गया? 2014 से 2021 तक मंहगाई और बेरोज़गारी ने सारे रिकार्ड तोड़ डाले हैं। पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का बढ़ना क्या किसी भी तर्क से जायज ठहराया जा सकता है? शायद नहीं। क्योंकि इस दौरान ऐसी कोई आपदा नहीं आयी है जिससे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी आयी हो। कोरोना को लेकर भी आज जो स्थिति सरकार के फैसलों के कारण खड़ी हुई है उसमें भी अब बिमारी से ज्यादा राजनीति की गंध आनी शुरू हो गयी है। जिस ढंग से मौद्रीकरण के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को प्राईवेट हाथों में सौंपने का ताना बाना बुना गया है उसका असर बहुत जल्द मंहगाई और बेरोज़गारी की बढ़ौत्तरी के रूप में सामने आयेगा यह तय है। उस समय आम आदमी कितनी देर शांत होकर बैठा रहेगा यह कहना कठिन है क्योंकि यह कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी आदमी केवल चार वर्ष के लिये निवेश करके आपकी संपत्ति की दशा–दिशा सुधारकर उसे आपको वापिस कर देगा।

वैसे तो इक आंसू भी बहा कर हमे ले जाए ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता

कुलदीप शर्मा

ऊना दिवस पर विशेष

कोई भी प्रशासनिक या भौगोलिक इकाई मानचित्र पर अलग रंग में खिंचा भूखंड नहीं होती। यह अपने लोगों के सपनों आकाँक्षाओं और संघर्षों का जागृत प्रतिबिम्ब होती है। इसी तरह भौगोलिक सीमाओं में बंधा ऊना जिला भी महज़ एक प्रशासनिक या राजनीतिक इकाई मात्र नहीं है। लगभग साढ़े पांच लाख वाशिंदों के दिलों की धडकन से स्पन्दित होता है यह भूभाग जो अपनी तमाम खूबियों और खामियों के चलते एक बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक धरोहर को अपने में सँजोए हुए है। पहली सितम्बर 2021 बुधवार के दिन यह जिला अपना 49वां जन्मदिन मना रहा है। अपने अस्तित्व के इस पायदान पर यह जिला न केवल प्रौढ़ बल्कि एक जिम्मेदार सोच को प्रतिबिम्बित करता है बल्कि समय के साथ कदमताल करते हुए यह देश की मुख्यधारा में अपनी भूमिका नियत करने को भी तत्पर है। वास्तव में यह जिला भी देश के दूसरे जिलों की तरह अपने संघर्षों, अपनी दुश्वारियों, अपने भाग्य और दुर्भाग्य के साथ अपनी जिजीविशा साथ लिए चल रहा है। फिर भी एक बात निश्चित है कि हिमाचल का मुख्यद्वार कहलाने वाले इस जिला की सोंधी मिट्टी की महक में गजब की कशिश है। आकर्षण का ऐसा जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है। ऊना एक किस्सा है जिसे सुनना शुरू करो तो बस सुनते ही चले जाने का मन करता है, एक ऐसी किताब है जिसे जितना पढ़ो उतनी जिज्ञासा बढ़ती है, एक ऐसा लोकगीत है जो बुज़ुर्गों के होंठों से आधुनिक पीढ़ियों के लबों पर उतरा है। एक मेला है जहाँ भाई बिछुड़ते नहीं आकर मिल जाते है, ऐसा है ऊना। यहाँ जो भी आता है यहाँ के लोकजीवन के अक्खड़पन और कुछ हद तक अटपटेपन के बावजूद इसके मोहपाश में ऐसा बंध जाता है कि इसे अपना स्थायी ठौर–ठिकाना बना लेता है। यहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं कि–

''वैसे तो इक आंसू भी बहा कर हमे ले जाए
ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता''

इसके उत्तर में सोलासिंगी धार एक तनी हुई प्रत्यंचा की तरह बिलासपुर और हमीरपुर की सीमाओं को छूती हुई पश्चिम में गोबिंद सागर की लहरों में अपना अक्स देखती है। इसके दो ऊँचे श्रृंगों पर अकेले और उदास बैठे प्राचीन किले सावन भादो नहाते है और अपने किसी जर्जर हिस्से की आहुति इतिहास के गहरे कुंड में डाल देते हैं। ये किले वर्षो से इस आस में बैठे है कि इधर भी आए कोई। ऊना की अधिकांश सीमा रेखा जो पंजाब के रोपड़ व होशियारपुर से सटी है, एक अलग तरह की मिश्रित संस्कृति की वाहक है। 1972 से अस्तित्व में आए इस जिला की बोली और भाषा भी ऐसे ही सांस्कृतिक सम्मिश्रण का परिणाम है, और इसी तरह का यहाँ का साहित्यिक वातावरण है। दरअसल जिला ऊना जमीनी हदों में सिमटा भूभाग नहीं एक जीवंत मानव समुदाय की सांझी कल्पनाओं का समुच्चय है। यहाँ के लोग जीवनयापन की मुश्किल स्थितियों और प्राकृतिक जटिलताओं के चलते, सहज ही जुझारू प्रकृति के हैं और अपने लिए कठिनाइयों के बीहड़ में भी जिंदगी के रास्ते खोज लेने का हुनर जानते हैं। अभाव और संघर्ष इनकी सवेदनाओं को कुंठित नहीं कर पाते। पारम्परिक तीज त्योहारों और उत्सवों पर यहाँ का जनजीवन अपने बेहतरीन रंगों में अपनी सामाजिकता व्यक्त करता है। इन सारी अच्छाइयों को देखने के लिए यहाँ के करीब आना बहुत जरूरी है। ऊना की साहित्यिक बिरादरी यहाँ के लोगों के जीवन और उसकी आन्तरिक बुनावटों को बड़े नजदीक से देखती है और उन्हें शब्दों में बांधती है। ऊना जिला के भाषा विभाग के अभिलेखों में यहाँ के साहित्यिकों की संख्या सौ से अधिक है, जो कि किसी भी जिला के लिए संतोषजनक स्थिति है। अधिकतर साहित्यिकार मुख्यतः कविता में ही अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को केन्द्रित रखते हैं, बाकि विधाओं जैसे कहानी संस्मरण, उपन्यास, नाटक, अनुवाद आदि कम–ज़–कम इस जिला में अब तक गौण ही रहे हैं। यहाँ की प्रमुख लोकसेवी संस्था हिन्मोत्कर्ष जन कल्याण परिषद पहले साहित्य एवं जनकल्याण परिषद हुआ करती थी और इसके संस्थापक कंवर हरी सिहं जी, साहित्यिक अभिरुचियों के स्वामी थे। उन्होंने अपनी सामाजिक सजगता और संवेदनशीलता के चलते हिमोत्कर्ष संस्था को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान दी, बल्कि अपने क्रियाकलापों का दायरा इतना विस्तृत किया कि ऊना की गतिविधियों की धमक देश भर में सुनी जा सकती थी। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जनकल्याण के कार्य बढ़ जाने से केवल सांस्कृतिक और जन कल्याण के कार्यो पर फोकस रहा। एक विशुद्ध साहित्यिक संस्था 'अभिव्यक्ति' है जो समय समय पर साहित्यिक आयोजन करती है और साहित्य की तमाम विधाओं के उन्नयन के लिए प्रयासरत है। 'अभिव्यक्ति' ने समय समय पर कहानी उत्सव और नाटक मंचन के क्षेत्र में भी थोडा किन्तु महत्वपूर्ण काम किया है। ऊना जिला के प्रख्यात शायर जाहिद अबरोल की दो पुस्तकों का विमोचन भी अभिव्यक्ति द्वारा किया गया जिसमे देश भर से नामचीन लोगों ने कार्यक्रमों में शमूलियत की थी। कुल मिलाकर ऊना का साहित्यिक वातावरण खुशगवार है। प्रशासन, मीडिया और सृजनशील लेखकों का परस्पर तारतम्य लेखकीय प्रतिभाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है। यहाँ के कई रचनाकार राष्ट्रीय साहित्यिक परिदृश्य पर भी खासे सक्रिय हैं। कोरोना काल में गतिविधियों पर भले ही थोडा विराम लगा हो पर सृजनकार्य अनवरत चलता रहा। कोरोना ने ऊना को पिछले दो वर्षो में कुछ ऐसे ज़ख्म दिए है, जिनका उपचार सम्भव नहीं है। इसने हमसे चार ऐसे व्यक्तित्व छीन लिए जो ऊना की धरती को अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता से गौरवान्वित कर रहे थे। इनमे हिमोत्कर्ष संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कंवर हरी सिंह, कवि और प्रमुख शिक्षाविद श्री ईश्वर दुखिया, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता राना शमशेर सिंह, और संस्कृत के विद्वान् डॉ. भक्तवत्सल इस दौरान हमसे छिन गये। इस अपूर्णीय क्षति को याद करते हुए मन उदास होता है किन्तु साथ ही ऊना के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद भी जागती है कि अतीत में इन दिवंगत विभूतियों का जो अमूल्य मार्गदर्शन यहाँ के लोगों को मिला है उसकी लौ में साहित्यिक और सामाजिक कार्य अनवरत चलते रहेंगे. देवी–देवताओं, साधू–संतों, पीरों–फकीरों, कवियों लेखकों, प्रशासकों–सियासतदानों, संपादकों, पत्रकारों की यह भूमि निरंतर प्रगति पर अग्रसर रहे, ऐसी कामना सिर्फ रिवायती नहीं हो सकती। इस जिला के जन्मदिन पर एक अकिंचन की प्रार्थना है। इस जिला के लिए एक साथ अभिशाप और वरदान के रूप में बहने वाली स्वां नदी अपनी मर्यादा के तटबंध न तोड़े, खनन की ताबड़तोड़ मार के चलते इसके सहज सौन्दर्य को दाग न लगें, पुलिस और अपराधी आमने सामने ही रहें अगल बगल नहीं। **''बचपन, सुरक्षित रहे, खिलखिलाता रहे, यौवन शीलयुक्त हो, बलहीन के पक्ष में हो, खुद्दारी और मर्यादा के गहनों से सुसज्जित रहे, और बुढ़ापे की लाठी बने लठैत नहीं, बुढ़ापा अपने अतीत पर गर्व कर सके और भविष्य पर भरोसा''** बस यही दुआ है ऊना के जन्मदिन पर ऊना के लिए।

जलियांवाला बाग–अमिट स्मृति

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस साल 28 अगस्त को अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अंग्रेजों द्वारा किये गए भीषण नरसंहार की घटना के एक सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद, देश इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठा सकता है। भारत ने सदियों से बहुत सारे आक्रमणों का सामना किया है, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। प्रत्येक आक्रमण के बाद जिन्दगी चलती रही। यह दृष्टिकोण लोकप्रिय पंजाबी कहावत – खादा पीता लहे दा, बाकी अहमद शाहे दा (जो कुछ भी उपलब्ध है, खाते – पीते रहो) (शेष को अहमद शाह अब्दाली लूट ले जाएगा) में परिलक्षित होता है। लेकिन यह कहावत जलियांवाला बाग त्रासदी को लेकर सिद्ध नहीं हो पाई, क्योंकि इसे लोग कभी भुला नहीं पायेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग एक हजार निर्दोष लोगों को ब्रिटिश ब्रिगेडियर – जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बेरहमी से गोलियों से भून डाला था। ये लोग 13 अप्रैल 1919 को खुशी के त्योहार, बैसाखी को मनाने के लिए इकट्टा हुए थे। इस नरसंहार ने घायल राष्ट्र की स्मृति पर एक दुखद व अमिट छाप छोड़ी है।

इतिहास की इस त्रासदी के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा कई पुस्तकें लिखी गयी हैं। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम को लागू करना, पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा, पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट – गवर्नर माइकल ओ 'डायर की भूमिका, रेजिनाल्ड डायर द्वारा हत्याकांड को अंजाम देना और उसके बाद गठित हंटर समिति द्वारा सभी दोषियों को दोषमुक्त करना आदि ऐसी घटनाएं हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं और जिनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यह अंग्रेजों की एक सुनियोजित गहरी साजिश थी, जिसके तहत भारतीयों को कुचलने के लिए अमानवीय कृत्यों के माध्यम से आतंक का राज स्थापित किया गया, जो किसी भी सभ्य देश के लिए अकल्पनीय रूप से शर्मनाक स्थिति थी। अंग्रेजों के कार्यों के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के मनोविज्ञान को समझना होगा। तभी यह स्पष्ट हो पायेगा कि आकस्मिक रूप से होने वाली यह अकेली घटना नहीं थी, जो एक रुग्ण दिमाग के अविचारित कार्यों के कारण घटित हुई थी।

भारत के 1857 के पहले स्वतंत्रता आन्दोलन बाद से, अंग्रेज बुरी तरह भयभीत हो गए थे। उनके शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों की किसी भी पुनरावृत्ति की संभावना ने उन्हें बहुत डरा दिया था। 20वीं सदी की शुरुआत में लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जैसे नेताओं को निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन इससे भी अंग्रेजों का भय कम नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक नेताओं के अपेक्षाकृत नरम रवैये के आधार पर उन्होंने सोचा कि अत्यधिक प्रताड़ना के उपाय से वे राष्ट्रीय भावना के उदय को आसानी से दबा सकते हैं, ताकि उनका शासन निरंतर जारी रहे। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने से अंग्रेज पूरी तरह बेखबर रहे। प्रथम विश्व युद्ध (1914 – 1918) के दौरान ब्रिटेन तथा इसके सहयोगी देशों के पक्ष में भारतीय जनता और भारतीय सैनिकों की बहादुरी के प्रति भी अंग्रेज पूरी तरह कृतघ्न बने रहे। एक छोटा – सा बहाना, यहां तक कि हड़ताल जैसा एक शांतिपूर्ण विरोध भी उनकी बर्बर कार्रवाई के लिए पर्याप्त था।

अंग्रेजों की भयावह साजिश की झलक पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट – गवर्नर माइकल ओ'डायर के कार्यों में दिखाई पड़ती है, जिसने लोगों के अधिकारों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़े – लिखे वर्ग का अपमान किया गया, सैकड़ों को सलाखों के पीछे डाला गया और प्रेस का गला घोंट दिया गया। अप्रैल, 1919 के शुरू होने के साथ ही घटनाओं की शुरुआत हुई। लाहौर और अमृतसर में शांतिपूर्ण हड़तालों को बलपूर्वक तोड़ा गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। अधिकांश प्रमुख स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित कर दिया गया। लाहौर और अमृतसर के साथ – साथ कसूर और गुजरांवाला जैसी जगहों पर भी अत्याचार हुए। अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण लोगों को भड़काने का कोई मौका नहीं गंवाया। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई, जब अमृतसर में हुई फायरिंग के परिणामस्वरूप पांच यूरोपीय लोगों की मौत हो गयी और कुछ भारतीय छात्रों को पढ़ाने जाते समय शेरवुड नाम की

– अश्विनी अग्रवाल –

एक महिला को गली में पीटा गया। ऐसा लगता है कि इससे ब्रिटिश सम्मान बुरी तरह आहत हुआ, क्योंकि इसके बाद गांवों में भी पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को क्रूर तरीके से पीटा गया और खुह कोरियन वाली गली (कोड़े मारे जाने वाली सड़क) में रेंगने के आदेश दिए गए।

घटना से ठीक एक दिन पहले ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जालंधर से अमृतसर स्थानांतरित किया गया था। आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध की बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं मिल पायी। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने के लिए बड़ी संख्या में आस – पास के ग्रामीण इलाकों के किसान पहले ही अमृतसर में जमा हो गए थे। डायर दोपहर में अपने सैनिकों, जिनमें से कोई भी ब्रिटिश नहीं था, के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। मिनटों में 1650 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हो गए, जो तितर – बितर होने की कोशिश कर रहे थे। सटीक संख्या का कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि आधिकारिक और अनौपचारिक आंकड़ों के बीच एक बड़ा अंतर था। घावों पर नमक छिड़कने के लिए डायर ने आने – जाने पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ कर्फ्यू लगा दिया, ताकि घायलों की देखभाल न हो सके और मृतकों को वहाँ से हटाया न जा सके।

डायर द्वारा हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमेटी के सामने दिए गए जवाब न केवल अपराधी की मनःस्थिति को, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। समिति को यह बताते हुए डायर को खुशी हुई कि उनके कार्य पूरी तरह से सचेत रहते हुए और पूर्व नियोजित रणनीति के परिणाम थे। अगर जगह की बनावट ने उसे रोका नहीं होता, तो वह अधिक लोगों को गोली मारने के लिए बख्तर बंद वाहनों को मशीनगनों के साथ ले जाता। तत्कालीन सरकार द्वारा डायर के खिलाफ की गई एकमात्र कार्रवाई थी – उसे अपने सक्रिय कर्तव्यों से मुक्त करना, जबकि माइकल ओ 'डायर और चेम्सफोर्ड पूरी तरह से सभी अपराधों से मुक्त किये गए।

अंग्रेजों की नजर में डायर एक नायक था। अंग्रेजों के द्वारा उसकी बहाली के बहुत प्रयास किये जा रहे थे, लेकिन भारतीय पीड़ा बहुत अधिक थी। अंग्रेज भारतीयों की मनोदशा और दुखद घटना के दूरगामी परिणामों का आकलन करने में विफल रहे। युवा भारतीय, क्रूरता के इन कृत्यों का बदला लेने के लिए तैयार थे। महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 मार्च, 1940 को लंदन में माइकल ओ 'डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा देशभक्त क्रांतिकारियों को जलियांवाला बाग और उसके बाद की घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति ऋणी हैं। अमृतसर स्थित स्मारक हमेशा एक ऋणी राष्ट्र को, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले की याद दिलाएगा। यह राष्ट्रीय गौरव का एक स्मारक है और स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

शोधकर्ताओं ने हमारे निकटवर्ती ब्रह्मांड में आपस में विलीन हो रहे तीन महाविशाल ब्लैकहोल्स का पता लगाया

शिमला। भारतीय शोधकर्ताओं ने तीन आकाशगंगाओं से ऐसे तीन महा विशाल ब्लैक होल्स की खोज की है जो एक साथ मिलकर एक ट्रिपल सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस बनाते हैं। यह एक नई खोजी गई आकाशगंगा के केंद्र में एक ऐसा ठोस क्षेत्र है जिसमें सामान्य से बहुत अधिक चमक है। हमारे निकटवर्ती ब्रह्मांडों में हुई यह दुर्लभ घटना बताती है कि विलय करने वाले छोटे समूह बहुसंख्यक महाविशाल ब्लैक होल का पता लगाने के लिए आदर्श प्रयोगशालाएं हैं और ये ऐसी दुर्लभ घटनाओं का पता लगाने की संभावना को बढ़ाते हैं।

किसी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने के कारण महाविशाल ब्लैक होल का पता लगाना कठिन ही होता है, लेकिन वे अपने परिवेश के साथ समाहित होकर अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। जब आसपास से धूल और गैस ऐसे किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल पर गिरती है तो उसका कुछ द्रव्यमान ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है जिससे वह ब्लैक होल बहुत चमकदार दिखाई देता है। इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस – एजीएन कहा जाता है और ऐसे नाभिक आकाशगंगा और उसके वातावरण में भारी मात्रा में आयनित कण और ऊर्जा छोड़ते हैं। तदुपरांत ये दोनों आकाशगंगा के चारों ओर का माध्यम विकसित करने और अंततः उस आकाशगंगा के विकास और उसके आकार में वृद्धि में अपना योगदान देते हैं।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स) के शोधकर्ताओं की एक टीम जिसमें ज्योति यादव, मौसमी दास और सुधांशु बर्वे शामिल हैं ने कॉलेज डी फ्रांस कॉम्ब्स, चेयर गैलेक्सीज एट कॉस्मोलोजी, पेरिस, के फैंकोइस कॉम्ब्सइ साथ एनजीसी 7733 और एनजीसी 7734 की जोड़ी का संयुक्त रूप से अध्ययन करते हुए एक ज्ञात इंटर – एक्टिव आकाशगंगा एनजीसी 7734 के केंद्र से असामान्य उत्सर्जन और एनजीसी 7733 की उत्तरी भुजा के साथ एक बड़े चमकीले झुरमुट (DyEi) का पता लगाया। उनकी जांच से पता चला है कि यह झुरमुट आकाशगंगा एनजीसी 7733 की तुलना में एक अलग ही गति से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का यहाँ आशय यह भी था कि यह झुरमुट एनजीसी 7733 का

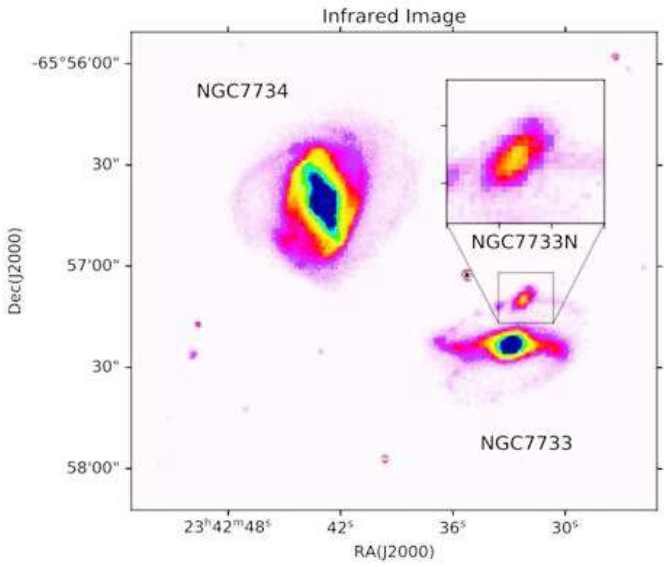

हिस्सा नहीं होकर उत्तरी भुजा के पीछे की एक छोटी किन्तु अलग आकाशगंगा थी। उन्होंने इस आकाशगंगा का नाम एनजीसी 7733 एन रखा है।

जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एक पत्र के रूप में प्रकाशित इस अध्ययन में पहली भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला पर लगे एस्ट्रोसैट अल्ट्रा – वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (यूवीआईटी), यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे एमयूएसई भी कहा जाता है, और जो चिली में बहुत बड़े आकार के दूरदर्शी (वेरी लार्ज टेलीस्कोप – वीएलटी) पर स्थापित किया किया गया है, से मिले आंकड़ों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में ऑप्टिकल टेलीस्कोप से प्राप्त (आईआरएसएफ) से प्राप्त इन्फ्रारेड चित्रों का उपयोग किया गया है।

अल्ट्रावायलेट – यूवी और एच – अल्फा छवियों ने निकल रही तरंगों के अतिम सिरे (टाइडल टेल्स) के साथ एक नए तारे के निर्माण का प्रकटीकरण करके वहां तीसरी आकाशगंगा की उपस्थिति का भी समर्थन किया जो एक बड़ी आकाशगंगा के साथ एनजीसी 7733 एन के विलय से बन सकती थी। इन दोनों आकाशगंगाओं के केंद्र (नाभिक) में एक सक्रिय महाविशाल ब्लैक होल बना हुआ है और इसलिए इनसे एक बहुत ही दुर्लभ एजीएन सिस्टम बन जाती है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, आकाशगंगा के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक आकाशगंगाओं की परस्पर क्रिया है जो तब होती है जब विभिन्न आकाशगंगाएं एक – दूसरे के निकट आती हैं और एक – दूसरे पर अपना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। इस तरह आकाशगंगाओं के आपस में मिलते समय उनमे विद्यमान महाविशाल ब्लैकहोल्स के भी एक – दूसरे के एक दूसरे के पास आने की सम्भावना प्रबल हो जाती हैं। अब द्विगुणित हो चुके ब्लैक होल्स अपने परिवेश से गैस का उपभोग करना शुरू कर देते हैं और दोहरी सक्रिय मंदाकिनीय नाभिक प्रणाली (एजीएन) में परिवर्तित हो जाते हैं।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) की टीम इसका घटना क्रम की व्याख्या करते हुए बताती है कि अगर दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं तो उनके ब्लैक होल भी अपनी गतिज ऊर्जा को आसपास की गैस में स्थानांतरित करके पास आ जाएंगे। ब्लैकहोल्स के बीच की दूरी समय के साथ तब तक घटती जाती है जब तक कि उनके बीच का अंतर एक पारसेक (3.26 प्रकाश – वर्ष) के आसपास न हो जाए। इसके बाद दोनों ब्लैक होल तब अपनी और अधिक गतिज ऊर्जा का व्यय नहीं कर पाते हैं ताकि वे और भी करीब आ सकें और एक – दूसरे में विलीन हो सकें। इसे अंतिम पारसेक समस्या के रूप में जाना जाता है। तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति इस समस्या को हल कर सकती है। आपस में विलीन हो रहे दोनों ब्लैकहोल ऐसे में अपनी ऊर्जा को तीसरे ब्लैकहोल में स्थानांतरित कर सकते हैं और तब एक दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं।

इससे पहले अतीत में कई सक्रिय एजीएन के जोड़ों का पता चला है। लेकिन तिहरी सक्रिय मंदाकिनीय नाभिक प्रणाली (ट्रिपल एजीएन) अत्यंत दुर्लभ हैं और एक्स – रे अवलोकनों का उपयोग शुरू किए जाने से पहले गिनती की ही ऐसी प्रणालियों के बारे में जानकारी थी। तथापि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) की टीम को उम्मीद है कि आकाशगंगाओं के छोटे विलय वाले समूहों में ऐसी ट्रिपल एजीएन प्रणाली और अधिक सामान्य होगी। हालांकि यह अध्ययन केवल एक ही प्रणाली पर केंद्रित है। परिणाम बताते हैं कि इस प्रकार विलीन होने वाले छोटे समूह कई महाविशाल ब्लैक होल्स का पता लगाने के लिए अपने आप में आदर्श प्रयोगशालाएं हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में संपूर्ण सितंबर माह में पूरे देश में 'विषय–आधारित' पोषण माह मनाया जाएगा

शिमला/शैल। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। 8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा

प्रारंभ किया गया, पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) कुपोषण की समस्या और मिशन-मोड में इसके समाधान की ओर देश का ध्यान केन्द्रित करती है। पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2021-2022 के बजट में मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) को एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया है, ताकि पोषण सामग्री, वितरण, पहुँच को मजबूत किया जा सके। विकासशील कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ऐसे परिणामों पर पहुँचा जा सके जो रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का पोषण करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

पोषण अभियान एक ''जन आंदोलन'' है जिसमें स्थानीय निकायों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है। सामुदायिक लामबंदी को सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, हर वर्ष सितंबर महीने को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।

इस वर्ष, जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ऐसे में त्वरित और गहन पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, समग्र पोषण में सुधार की दिशा में केंद्रित और समेकित दृष्टिकोण के लिए पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में विभाजित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर पूरे महीने कई गतिविधियों की योजना बनाई है।

निम्नलिखित तालिका में इस वर्ष अपनाए जा रहे विषयगत दृष्टिकोण को दर्शाती है:

तिथियां	विषय
1-7 सितम्बर	''पोषण वाटिका'' के रूप में पौधरोपण गतिविधि
8-15 सितम्बर	पोषण के लिए योग और आयुष
16-23 सितम्बर	अधिक जिम्मेदारी वाले जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों को ''क्षेत्रीय पोषण किट'' का वितरण
24-30 सितम्बर	एसएएम के बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण

इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला आंगनवाड़ियों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध स्थलों में सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए वृक्षारोपण अभियान पर केंद्रित होगी। पौधरोपण गतिविधियां पौष्टिक फलों के वृक्ष, स्थानीय सब्जियों और औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के पौधे लगाने पर केंद्रित होगी। कोविड टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए संवेदीकरण/जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। पोषण माह के दौरान (6 वर्ष से कम आयु के) बच्चों के लिए ऊंचाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन की जानकारी को सामने लाने के लिए स्लोगन लेखन और इसे पकाने की विधि की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सरकार और कॉर्पोरेट निकायों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यस्थलों पर ''5-मिनट योग प्रोटोकॉल'' (ok)-ब्रेक या योग विराम) पर सत्र होंगे, इसके अलावा क्षेत्रीय/स्थानीय भोजन के महत्व पर जागरूकता अभियान, पोषण किटों का वितरण जिसमें क्षेत्रीय पोषक तत्व से भरपूर भोजन (जैसे सुकड़ी-गुजरात, पंजीरी-पंजाब, सत्तू-बिहार, चिक्की-महाराष्ट्र) शामिल होंगे साथ ही एनीमिया शिविर, एसएएम बच्चों की ब्लॉकवार पहचान के लिए अभियान, बच्चों में एसएएम के प्रसार से निपटने के लिए एक पहल के रूप में 5 वर्ष की आयु तक के एसएएम बच्चों के लिए पर्यवेक्षण पूरक आहार कार्यक्रम, तीव्र कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन के लिए संवेदीकरण और एसएएम बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का वितरण भी किया जाएगा।

पोषण माह के दौरान, पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर तक संचालित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे कार्यान्वयन विभाग/एजेंसियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से आशा, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज विभाग, और ग्रामीण विकास के माध्यम से स्वयं सहायता समूह इन गतिविधियों को अंजाम देंगे और महिलाओं एवं बच्चों का एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरे महीने समग्र पोषण का संदेश फैलाएंगे।

एक विशिष्ट और समग्र लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया, पोषण अभियान कुल मिलाकर छोटे बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ-साथ पति, पिता, सास और समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) सहित परिवार के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण पोषण व्यवहार के संबंध में पोषण संबंधी जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ाने का सकारात्मक इरादा रखता है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण अभियान के समग्र लक्ष्यों को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से त्वरित रूप से अर्जित करना है।

एक दिन में दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक के साथ जीत का क्रम बरकरार

अवनि लेखरा निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय महिला बनीं

सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक (एफ 64) प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

देवेंद्र, सुंदर और योगेश टारेगट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) का हिस्सा रहे हैं

शिमला। एक दिन में एक नहीं बल्कि पांच पदकों की जीत के साथ भारत के लिए यह सोमवार शानदार रहा है। भारत की अवनि लेखरा देश के लिए निशानेबाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली इतिहास में पहली भारतीय महिला बन गईं और सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक (एफ 64) प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही एथलेटिक्स में भाला फेंक और डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धाओं में भारत का वर्चस्व बना हुआ है।

रविवार के शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए, भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र ने टोक्यो में अपना तीसरा पैरालंपिक पदक और 64.35 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ एफ 46 श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पदक जीता। देवेंद्र ने भारतीय खेल प्राधिकरण- गांधी नगर में प्रशिक्षण हासिल किया है। इसके अलावा, राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर के सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।

इस महीने टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले, सुंदर ने कहा था कि वह अच्छे फॉम में है और वह पदक जीतने के लक्ष्य के साथ टोक्यो पैरालंपिक जा रहे हैं, जिसमें वह रियो ओलंपिक में चूक गए थे।

उन्होंने कहा था, 'मैं 2016 से टीओपीएस से जुड़ा रहा हैं और शुरुआत से ही टीओपीएस और साई ने खासा समर्थन किया है, यहां तक कि हाल में वेट रनिंग और एक जैवलीन खरीदने में वित्तीय सहायती की गई। इससे मुझे भाला फेंकने में खासी सहायता मिली। मैं समर्थन का आभारी हूं, जो मुझे उपलब्ध कराया गया है।'

देवेंद्र और सुंदर भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) का हिस्सा रहे हैं और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण किया गया है। सुंदर के मामले में प्रोस्थेसिस, उपकरण और कोच शुल्क अनुदान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

दो भाला फेंक खिलाड़ी टोक्यो स्टेडियम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पहली बार ओलंपिक पहुंचे योगेश कथूनिया स्टेडियम की दूसरी तरफ दिन का तीसरा पदक सुनिश्चित कर रहे थे।

योगेश ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो की एफ 56 श्रेणी में 44.38 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ भारत के लिये रजत पदक जीता और इस प्रतिस्पर्धा में वर्चस्व बनाए रखा।

2017 में डिस्कस थ्रो बैक करने वाले हरियाणा के युवा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2019 में कांस्य पदक जीता था और 1984 के ओलंपिक में जोगिंदर सिंह बेदी द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद डिस्कस थ्रो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं।

देवेंदर और सुंदर की तरह, योगेश भी साई की टीओपीएस पहल का हिस्सा रहे हैं, जिसने योगेश के लिए चार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में वित्तपोषण किया और स्पोर्ट्स साइंस के समर्थन के साथ राष्ट्रीय कोचिंग शिविर उपलब्ध कराए गए।

सभी तीनों एथलीट्स को टोक्यो पैरालंपिक में पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा था और वह उम्मीदों पर खरे उतरे।

2 अक्तूबर से आरंभ होगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्तूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का आयोजन करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आयोजित स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली यात्रा के 50 वर्षों में आम आदमी के योगदान का जश्न मनाया जाएगा। सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य भर में 51 कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा लगभग दो महीने के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर 25 जनवरी, 2022 को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, चार उप. समितियां भी गठित की गई हैं जिनमें स्वर्णिम रथ खरीद समिति, सूचनाए शिक्षा एवं संप्रेषण समिति, सोशल मीडिया समिति और बजट समिति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 25 जनवरी से राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में राज्य के विकासात्मक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, सामाजिक कार्य, संस्कृति, साहित्य आदि में उपलब्धि हासिल करने वाले सफल लोगों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम रथ को राज्य के विकास के गौरवशाली इतिहास प्रदर्शित करने के लिए नवीनतम उपकरणों से लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख विभाग जैसे शिक्षाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, वन और बिजली विभाग भी इन पचास शानदार वर्षों के दौरान हुए विकास का प्रदर्शन करेंगे।

जय राम ठाकुर ने जिला प्रशासन को रथ यात्रा से सम्बन्धित कार्य योजना और अन्य जानकारी अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस रथ यात्रा के सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, युवक मण्डलों, महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ -चढ़ कर इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और स्वर्णिम रथ यात्रा खरीद समिति के अध्यक्ष त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रत्येक परिवार को इस भव्य आयोजन से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को इससे अपनेपन का अहसास हो सके।

अधिकारी नवाचार कार्यक्रमों और परिणामोन्मुखी नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य करें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। अधिकारियों को नवाचार विचारों के साथ आगे आना चाहिए और लीक से हट कर सोचना चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवीन कार्यक्रम और परिणामोन्मुखी नीतियां बनाई जा सकें। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरू भवन का लोकार्पण करने के उपरान्त हिमाचल प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कही। इस भवन का निर्माण 4.34 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हिपा के ई-ऑफिस और वॉल-ई का भी शुभारम्भ किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है और सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान करना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि वह आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य प्रदान किया गया है उसे प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी धारणा बनाई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अधिक उत्साह से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से वे लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और योजनाओं का लाभ सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को मिले। अधिकारियों को लाभार्थियों तक पहुचना चाहिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण युवा अधिकारियों के लिए है, जो सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके बुनियादी ज्ञान, कौशल और व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से उनकी दक्षता और संवेदनशीलता पर केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक, पुलिस, राजस्व, विकास, कर-प्रशासन और अन्य सम्बन्धित विभागों में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत सरकारी विभागों के सामान्य कार्य के अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने नागरिक/राजस्व प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, विशिष्ट अधिनियमों पर व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हिपा की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता की शिकायतों का घरों के निकट निवारण सुनिश्चित किया, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत न आने वाले लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के परिवारों को 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरू की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. राजीव बंसल और डॉ. मनोज शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सिटीजन इम्पॉवरमेंट-ए स्टडी ऑफ ई-गवर्नेंस सर्विसिज और डॉ. राजीव बंसल द्वारा लिखित पुस्तक स्टैपिंग स्टोनज-ए कम्पेंडियम ऑफ केस स्टडीज का भी विमोचन किया।

सचिव प्रशासनिक सुधार एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संदीप भटनागर ने कहा कि प्रशिक्षुओं को सरकारी कार्य की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिपा के पास योग्य और प्रशिक्षित इन-हाउस फैकल्टी है, जो सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले नए अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करने में रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यस्कों की शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीके को समझते हुए, हिपा का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्रशिक्षण के उन सभी तरीकों का उपयोग किया जाए जो एक व्यस्क की सीखने-समझने की क्षमता के अनुसार हों।

हिपा के निदेशक विवेक भाटिया ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि नया परिसर राज्य सरकार के अधिकारियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 19 नवनियुक्त एचएएस (हिमाचल प्रशासनिक अधिकारियों) और अन्य सिविल सेवा अधिकारियों ने 8 सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स में भाग लिया, जो एक जुलाई से शुरू हुआ और इस माह की 28 तारीख को समाप्त है। इन अधिकारियों में नौ हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी, एक हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारी, दो तहसीलदार, तीन खंड विकास अधिकारी, दो जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी, एक जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और एक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए हिपा में खेल परिसर का निर्माण किया जाना चाहिए।

जन सहयोग से 1904 हेक्टेयर वन भूमि में 12.62 लाख पौधे रोपित किए गए

शिमला। प्रदेश में वन सम्पदा के संरक्षण और विकास के लिए समर्पित हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा हर वर्ष जुलाई माह में मॉनसून के दौरान राज्य में वन महोत्सव मनाया जाता है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन के साथ ही पूरे प्रदेश में वनीकरण के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पौधरोपण कार्य आरम्भ कर दिया जाता है।

लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय, वृत स्तरीय व मण्डल स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 20 जुलाई, 2021 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। वन विभाग ने इस वर्ष पूरे प्रदेश में 14000 हेक्टेयर वन भूमि पर एक करोड़ 40 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पौधरोपण का कार्य विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं व बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। पौधरोपण की सफलता और सुरक्षा के लिए जन-सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष वन विभाग ने पौधरोपण कार्यों में जन-सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नई पहल करते हुए पंचायत स्तर पर जनता द्वारा चयनित जन प्रतिनिधियों की सबसे सूक्ष्म इकाई वार्ड सदस्यों को पौधरोपण अभियान में शामिल किया है।

इस पहल के तहत वन विभाग प्रत्येक पंचायत, नगर निकाय, एवं नगर पंचायत वार्ड में प्रत्येक वार्ड सदस्य को 51 स्थानीय प्रजाति के पौधे वितरित किए जा रहे हैं, जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं और आसानी से बढ़ते हैं। इन पौधों को स्थानीय लोगों की सहायता से उपलब्ध वन भूमि, शामलात भूमि या निजी भूमि पर रोपित किया जा रहा है। वन विभाग ने प्रदेश में लगभग 7000 वार्ड सदस्यों को 3,57,000 पौधे रोपित करने के लिए दिए हैं। यह पहली बार हुआ है कि वार्ड सदस्यों के माध्यम से पौधरोपण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोग वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर पौधरोपण कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस प्रकार के जन सहयोगी अभियानों के फलस्वरूप वन विभाग को प्रदेश के हरित वन आवरण की वृद्धि में सफलता मिली रही है। वन विभाग द्वारा जन सहयोग से 20 जुलाई से अब तक 1904 हेक्टेयर वन भूमि पर 456 स्थानों पर 12,62,622 पौधे रोपित किए जा चुके हैं।

राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा भी वन विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर इस वर्ष पूरे प्रदेश में एक लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। रेडक्रॉस सोसाइटी ने अब तक 73 स्थानों पर 145 हेक्टेयर भूमि पर 95548 पौधे रोपित किए हैं।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. के जवान, नाबार्ड एवं अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी वन विभाग के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में पौधरोपण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पौधरोपण को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को पौधरोपण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।

स्कूल के विद्यार्थियों में वन पर्यावरण के संरक्षण की भावना जागृत करने के लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना के लिए स्कूलों को एक निर्धारित वन क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा पौधे लगाने व उनकी देख-रेख के लिए आबंटित किया जा रहा है। वनों के प्रबंधन व संरक्षण के लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, एक बूटा बेटी के नाम योजना जैसी अन्य योजनाएं भी शुरु की हैं।

वन विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इन्हीं पौधरोपण कार्यक्रमों की सफलता के कारण ही हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों में हरित आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है।

अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हुई बजट में वृद्धि

शिमला। राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय प्रदेश और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के स्नेह से ही यह संभव हो पाया है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। भाजपा के कार्यकाल में ही अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बजट में वृद्धि की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लगभग 15,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश मकान अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए बनाए जाएंगे। इस अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं जैसे गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना और हिमकेयर से अनुसूचित जाति के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य की अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

विवादित कृषि कानूनो का परिणाम है सेब की कीमतों का कम होना

शिमला/शैल। मोदी सरकार द्वारा जून 2020 में लाये गये तीन कृषि कानूनों का प्रभाव अब हिमाचल के करीब पांच हजार करोड़ के सेब कारोबार पर भी प्रत्यक्षत: पड़ना शुरू हो गया है। इस समय प्रदेश में अंबानी एग्रो फ्रैश सेब का सबसे बड़ा खरीददार है। उसके प्रदेश में अपने स्टोर हैं और उनमें भारी भण्डारण क्षमता है जो कि सेब उत्पादकों के पास है नहीं। न ही सरकार ने अपने तौर पर कोल्डस्टोरों का निर्माण करवाया है। अब नये कृषि कानूनों के आने से उत्पादक और खरीददार एपीएमसी परिसरों से बाहर भी अपना उत्पाद बेचने और खरीदने के लिये स्वतन्त्र हैं। इस व्यवस्था से उन्हें अपने कारोबार की 1% फीस एपीएमसी को देने की आवश्यकता है। इसलिये अंबानी सीधे उत्पादकों से ही यह खरीद कर रहा है और अपने ही केन्द्रों पर उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग कर रहा है। इस व्यवस्था में वह सरकार को फीस देने से बाहर हो जाता है और यहीं पर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है। एग्रो फ्रैश का दावा है कि करीब बीस हजार उत्पादक उसके साथ सीधे जुड़ चुके हैं इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इसमें प्रदेश सरकार को कितना नुकसान पहुंचेगा।

सरकार के नुकसान के अतिरिक्त उत्पादकों का सीधा नुकसान इस कारण से हो रहा है कि इस बार सेब खरीद के रेट में ही सोलह रूपये प्रति किलो की कमी कर दी गयी है। जो सेब पिछले वर्ष 80 से 82 रूपये में खरीदा गया था उसमें अब 16 रूपये की कमी करके खरीदा जा रहा है। रेट में कमी के लिये सेब की गुणवत्ता को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन जब इन रेटों के निर्धारण को लेकर अंबानी के ऐजैन्टों के ही दो अलग – अलग ब्यान सामने आ गये तब यह स्पष्ट हो गया कि रेट कम करने में अंबानी का ही प्ले है और लदानी – अंबानी गठजोड़ के खिलाफ नारे लग गये। लेकिन इस सारे प्रकरण पर जयराम सरकार ने खामोशी अपना ली और उत्पादकों को यह राय दे डाली कि वह कुछ समय के लिये सेब का तुड़ान ही रोक दें। सरकार की इस भूमिका पर उत्पादकों का रोष और बढ़ना स्वभाविक है क्योंकि उसका सीधा नुकसान हो रहा है।

स्मरणीय है कि अंबानी ने पिछले वर्ष रोहडू के मैंदली में सितम्बर माह में सेब खरीदा था और यहीं पर इसकी पैकिंग की गई बाद में इसी सेब को चण्डीगढ़ के एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्र्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाईसैन्स लेकर छ: सेब का पैकेट 196 रू. में बेचा गया। इस तरह सेब उत्पादक से जो सेब 80 – 82 रूपये में खरीदा उसे उपभोक्ता को 196 रूपये में बेचा गया। सरकार इस सारे खेल में मूक दर्शक की भूमिका में तब भी रही और आज भी है। आज तो उत्पादक के रेट भी 16 रूपये कम कर दिये गये हैं। सेब उत्पादक और उपभोक्ता का यह नुकसान हर वर्ष इसी तरह होने वाला है। क्योंकि नये

कृषि कानूनों में उत्पादक और उपभोक्ता को कहीं कोई संरक्षण हासिल नहीं है। बल्कि अब तो विदेशी सेब के आने से बाजार में असन्तुलन और भी बढ़ेगा। क्योंकि विदेश से आने वाले सेब को आयात शुल्क से मुक्त रखा गया है। यही नहीं विदेश से आने वाले इस सेब की बाजार कीमत पहले से ही तय कर दी जाती है और इसकी खरीद कीमत का भुगतान अग्रिम में ही किया जाता है।

स्व. नरेन्द्र बरागटा ने विदेशी सेब के आयात शुल्क मुक्त होने को लेकर केन्द्र सरकार को इसके विरोध में कई बार पत्र लिखें हैं। विदेशी सेब के इस तरह लाये जाने से स्थानीय उत्पादकों का नुकसान होगा इसको लेकर वह लगातार चिन्तित रहे। आढ़तीयों द्वारा किये जा रहे शोषण को लेकर भी वह दिल्ली की सरकारों से लम्बा पत्राचार कर चुके हैं। सेब को लेकर जिन खतरों के प्रति वह बागवानों को लगातार जागरूक करते रहे हैं आज उन्हीं की पार्टी की सरकार में सेब उत्पादक का शोषण हो रहा है और सरकार चुपचाप यह सब देख रही है क्योंकि हस्तिनापुर से बंधी है। आज सेब उत्पादक को स्पष्ट हो गया है कि इन कृषि कानूनों से उसका लगतार नुकसान होना तय है। इसलिये इन कानूनों की वापसी के लिये उसे किसान आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाना आवश्यक हो जायेगा यह अब उसे समझ आ गया है।

टिकैत के आने से किसान आन्दोलन ने लिया प्रदेश में आकार

- 13 को धरने प्रदर्शनों का एलान
- महेंद्र सिंह को हटाने की उठी मांग
- भारद्वाज भी आये निशाने पर

शिमला/शैल। हिमाचल में सेब का करीब पांच हजार करोड़ का कारोबार होता है। सेब उत्पादकों को इस मुकाम तक पहुचाने में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कारोबार से बागवान और सरकार दोनों कमाई करते रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना काल में जून 2020 में तीन कृषि कानून लाकर किसान-बागवान और सरकार तीनों के हित्तों को नजरअन्दाज करके कृषि क्षेत्र को प्राईवेट सैक्टर के हवाले करने का जो खेल रचा है उसकी आंच में आज हिमाचल का सेब उत्पादक भी बुरी तरह झूलस कर रह गया है। जब अंबानी ने सेब की खरीद कीमतों में पिछले वर्ष के मुकाबले 16रू किलो की कमी कर दी तब बागवानों को इसमें कंपनीयों की होने वाली भूमिका का अहसास हुआ। यह कीमतें कम करने पर जयराम सरकार अंबानी से सवाल-जवाब करती इसकी बजाये बागवानों को ही सलाह दे डाली कि वह कुछ समय के लिये तुड़ान ही रोक दें। मुख्यमन्त्री की इस राय से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार इसमें कुछ भी करने वाली नहीं हैं।

ऐसे समय में किसान नेता टिकैत ने प्रदेश के बागवानों को आगाह किया कि यदि वह इस समय ''कंपनी राज'' के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने से चुक गये तो एक दिन सेब के बागीचों पर भी असम के चाय बागानों की तरह कंपनीयों का कब्जा हो जायेगा। टिकैत ने जब कृषि कानूनों के खतरों के बारे में प्रदेश के किसानों-बागवानों को विस्तार से समझाया उसके बाद प्रदेश में किसान आन्दोलन के आकार लेने की संभावनाओं को बल मिला है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों व बागवानों के मुद्दों को लेकर 13 सितंबर को तहसील व खंड स्तर पर आंदोलन छेड़ने का एलान किया है। मोर्चा ने कहा कि इस तरह तहसील व खंड स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर सरकार ने किसानों व बागवानों की मांगों की पर गौर नहीं किया तो 26 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में गठित संयुक्त किसान मोर्चा की राजधानी में अहम बैठक हुई व प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर पूरा गुब्बार निकाला गया। मोर्चा की इस बैठक में आए किसान व बागवान नेताओं ने कहा कि मंत्री ने बागवानी व किसानी कोई दोष नहीं है। मोर्चा ने एक आवाज में कहा कि यह अदानी, लदानी (खरीददार) और आढ़तियों का पक्ष लेना जैसा है। यह बागवान व किसान विरोधी रुख है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में अन्यों के अलावा कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और वामपंथी माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी शिरकत की।

मोर्चा के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि प्रदेश में लगभग 89 फीसद जनता गांव में रहती है व इसमे अधिकांश का रोजगार व आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व बागवानी ही है। आज देश मे कृषि के संकट के चलते प्रदेश के किसानों व बागवानों का संकट भी बढ़ रहा है। खेती में उत्पादन लागत कीमत निरन्तर बढ़ रही है और किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद का उचित दाम प्राप्त नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को मंडियों के विकास व किसानों के हितों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है वह अपने दायित्व के निर्वहन में विफल रही है। जिसके फलस्वरूप आज भी मंडियों में किसानों व बागवानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इनका शोषण बढ़ा है।

इस बैठक में दस मांगों पर सहमति बनी। मोर्चा ने कहा कि प्रदेश में अदानी व अन्य कंपनियों व मण्डियों में किसानों के शोषण पर रोक लगाए व प्रदेश में भी कश्मीर की तर्ज पर मण्डी मध्यस्थता योजना को पूर्ण रूप से लागू किया जाए व सेब के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत ए, बी व सी ग्रेड के सेब के लिए क्रमश: 60 रुपये 44 रुपये व 24 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये।

प्रदेश की विपणन मण्डियों में ए पी एम सी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मंडियों में खुली बोली लगाई जाए व किसान से गैर कानूनी रूप से की जा रही मनमानी वसूली को तुरन्त समाप्त किया जाए। जिन किसानों से भी यह वसूली की गई है उन्हें इसे वापिस किया जाए।

चौहान ने कहा कि सेब व अन्य फलों, फूलों व सब्जियों की पैकेजिंग में इस्तेमाल किये जा रहे कार्टन व ट्रे की कीमतों में की गई भारी वृद्धि वापिस की जाए व प्रदेश में भारी ओलावृष्टि, वर्षा, असामयिक बर्फबारी, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाए। प्रदेश की सभी मंडियों में सेब व अन्य फसलें वजन के हिसाब से बेची जाएं।